ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, शनिवार 31 मई 2025

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 2 अंक 63

देश में कोरोना से 20 की मौत, 3207 एक्टिव केस:कर्नाटक सरकार का आदेश- बच्चों को सर्दी-खांसी या बुखार हो तो स्कूल न भेजें



देशभर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3207 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केसेज के मामले में दूसरे नंबर पर है। शुक्रवार को राज्य में 84 नए केस सामने आए, यहां अब 681 मरीज हैं। देश के 60 फीसदी एक्टिव केस इन्हीं दो राज्यों में हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। कर्नाटक के मैसूर में शुक्रवार को 63 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से यह तीसरी मौत है। इसके अलावा, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मई को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में भी एक-एक मौत की पुष्टि की।

इस बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें माता-पिता से अपील की है कि अगर बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार या कोविड जैसे लक्षण हों तो उन्हें स्कूल न भेजें।

मिजोरम में 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इस तरह का आखिरी मामला सामने आने के 7 महीने बाद कोविड के केस मिले। मिजोरम में कोविड-19 का आखिरी मामला अक्टूबर 2024 में सामने आया था, उस दौरान राज्य में 73 लोग वायरस से संक्रमित हुए थे।

उन्होंने बताया कि मरीजों का इलाज आइजोल के पास फल्कोन में जोरम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (ZMCH) में चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इंटीग्रेटेड रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) ने लोगों से न घबराने की बात कही है। IDSP ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, नियमित रूप से हाथ धोने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है।

जल्द ही UPI-ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा:जून से मिल सकती है नई सुविधा, इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा निकाल सकेंगे



24 न्यूज अपडेट

केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अगले महीने यानी जून में बड़े बदलाव की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है।

EPFO 3.0 के तहत, PF खाताधारकों को विड्रॉल कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। यह पूरी तरह से बैंक ATM कार्ड की तरह होगा। नई सुविधा के तहत एक तय रकम ही निकाली जा सकेगी। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी।

ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं?

इस नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।

CJI बीआर गवई ने योगी को बताया देश के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री



24 न्यूज अपडेट, नेशनल डेस्क। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में नई मल्टीलेवल पार्किंग और वकील चेंबर्स का भव्य उद्घाटन किया। यह उनकी CJI बनने के बाद प्रयागराज का पहला दौरा था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री बताया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। CJI गवई ने इलाहाबाद की भूमि को पावरफुल लोगों की भूमि करार देते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब बार और बेंच मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा, "अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचाना हमारा मौलिक कर्तव्य है।" सीएम योगी ने महाकुंभ के दौरान हाईकोर्ट की भूमिका की सराहना की और वकीलों के लिए बनाए गए एयर कंडीशंड चेंबर्स की सुविधाओं का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने योगी की प्रशंसा करते हुए कहा कि महाकुंभ में उनकी शानदार व्यवस्था के कारण ही आयोजन सफल रहा। उन्होंने कहा कि जल्दी और प्रभावी काम करने की कला सीखनी हो तो योगी से सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने इलाहाबाद बार एसोसिएशन की तारीफ करते हुए नई बिल्डिंग के सदुपयोग पर जोर दिया।

नई मल्टीलेवल पार्किंग पाँच मंजिला है, जिसमें 2300 चारपहिया और 1500 दोपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। दिव्यांगजन के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, 2300 वातानुकूलित चेंबर, कैंटीन, लाइब्रेरी, बैंक, एटीएम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। 26 स्वचलित सीढ़ियां और 24 लिफ्टें सुविधा को और बढ़ाती हैं, जिससे यह हाईकोर्ट परिसर एक अत्याधुनिक केंद्र बन गया है।

दिल्ली की रेखा सरकार के 100 दिन पूरे:CM बोलीं- खुद को आम आदमी बताने वाले सत्ता के लालच में आ गए



दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को दिल्ली सरकार ने विशेष कार्यक्रम '100 दिन सेवा के' आयोजित किया। इसमें बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर भी पहुंचे। उन्होंने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सवाल-जवाब किए। सरकार के 100 दिन के कामों के बारे में पूछा। JLN स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में रेखा गुप्ता ने कहा- जब रामलीला मैदान से आंदोलन शुरू हुआ, तो हजारों-लाखों लोग इसमें शामिल हुए। मैं भी शामिल हुई। सभी ने इसका समर्थन किया। वे लोग (AAP) जो कहते थे कि वे सत्ता के लालची नहीं हैं, वे इतने लालची हो गए कि उन्हें सत्ता के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों के बीच सड़कों पर काम कर रही है। मेरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि लगातार लोगों के बीच सड़कों पर काम करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर सेना पर सवाल उठाते थे। देश के दुश्मनों से हाथ मिलाते थे।

अनुपम खेर के सवाल पर उन्होंने कहा- मुझे दिल्ली इसलिए पसंद है कि क्योंकि यहां सांस्कृतिक विविधता है। दिल्ली के बारे में जो सबसे अच्छी बात यहां की एकता है। यह एक लघु भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत का रूप है। भारत के हर हिस्से के लोग दिल्ली में रहते हैं, और वे एक-दूसरे की परंपराओं और त्योहारों को एक साथ मनाते हैं।

दरअसल, 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सीएम पद की शपथ ली थी। वे दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वालीं 9वीं और चौथी महिला CM हैं। वे शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। 30 मई को उन्होंने दिल्ली को विकसित कर इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस और सुंदर शहर बनाने की घोषणा करते हुए 20 काम करने का दावा किया था।

भाजपा ने चुनाव से पहले दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाने का वादा किया था। चुनावी संकल्प पत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी कई घोषणाएं की थीं। लेकिन, दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि रेखा सरकार के 20 कामों के दावे के उलट जनहित के कामों की केवल 2 योजनाएं ही जमीन पर उतर पाई हैं। इनमें एक आयुष्मान भारत योजना है और दूसरी वय वंदना योजना।

VI का लॉस 6.6% घटा, 7166 करोड़ हुआ:चौथी तिमाही में रेवेन्यू 11,013 करोड़ रहा; कंपनी को बोर्ड से 20,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिली



24 न्यूज अपडेट

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 7,166 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा (कॉन्सोलिडेटेड नेट लॉस) हुआ है। सालाना आधार पर यह 6.63% घटा है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 7,675 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। जनवरी-मार्च तिमाही में ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 11,013 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में वोडाफोन आइडिया ने 10,606 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। सालाना आधार पर यह 3.83% बढ़ा है। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से मिली राशि को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है। VI ने शुक्रवार (30 मई) को जनवरी-मार्च तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए हैं।

कंपनी को बोर्ड से 20,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिली

साथ ही कंपनी के बोर्ड ने विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी भी दे दी है। कंपनी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबी हुई है।

बंगाल में साली का कटा सिर लेकर घूमा व्यक्ति:मंदिर के सामने पहुंचकर जयकारा लगाया

पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में एक व्यक्ति अपनी साली का कटा हुआ सिर लेकर इलाके में घूमते दिखा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी के दाएं हाथ में एक धारदार हथियार और बाएं हाथ में कटा हुआ सिर दिख रहा है। वह एक मंदिर के सामने जयकारा भी लगता है।

पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया- घटना बसंती थाना क्षेत्र के भरतगढ़ गांव की है। आरोपी का शुक्रवार रात को साली से झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर उसने धारदार दरांती से साली का सिर धड़ से अलग कर दिया।

पुलिस के कहा- हम घटना की जांच कर रहे हैं। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम भेजी गई है। महिला का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी आरोपी के पास से जब्त कर लिया गया है।

जस्टिस वर्मा कैश मामला, परिवार ही स्टोररूम इस्तेमाल करता था:जांच पैनल की रिपोर्ट में खुलासा; आग लगने के बाद नकदी हटाई



दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर अधजले नोट मिलने के मामले में नए खुलासे हुए हैं। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जिस स्टोर रूम में आग लगने के बाद जली नकदी मिली, वह जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में था।

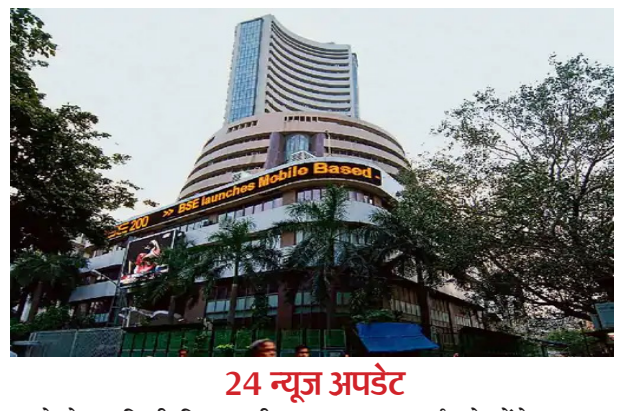
जांच समिति ने बंगले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, गवाहों और जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। समिति ने 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और फायर सर्विस के प्रमुख भी थे। दोनों अफसर आग लगने के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मार्च, 2025 की रात करीब 11:35 बजे आग लगने के बाद स्टोर रूम से नकदी हटाई भी गई थी।

अधजले नोट मिलने की खबर सामने आने के बाद उस समय के CJI संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 22 मार्च को पैनल बनाया था। पैनल ने 4 मई को CJI को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था।

रिपोर्ट के आधार पर CJI ने 'इन-हाउस प्रोसीजर' के तहत जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन थीं।

सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 पर बंद:निफ्टी 83 अंक लुढ़का, जोमैटो का शेयर 4.95% चढ़ा; सरकारी बैंकिंग शेयरों में 3% की तेजी



24 न्यूज अपडेट

हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार, 30 मई को सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 83 अंक की गिरावट रही, ये 24,751 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी रही। जोमैटो का शेयर 4.95% चढ़ा। SBI, HDFC बैंक, LT और बजाज फिनसर्व के शेयर भी 2% ऊपर बंद हुए। HCL टेक, टेक महिंद्रा और इंफोसिस समेत 14 शेयरों में 2% तक की गिरावट रही।

निफ्टी के 50 शेयरों में से 7 में तेजी और 43 में गिरावट देखने को मिली। NSE के सरकारी बैंकों का इंडेक्स 2.88% चढ़ा। जबकि, मेटल में 1.69%, IT में 1.15% और ऑटो में 0.98% की गिरावट रही।

माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास की विधायकी जाएगी:हेटस्पीच में 2 साल की सजा; कहा था- अफसरों का हिसाब-किताब होगा



माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई है। शनिवार को मऊ कोर्ट ने यह फैसला दिया। सजा के ऐलान के साथ ही अब्बास की विधायकी भी चली जाएगी। कोर्ट ने अब्बास के साथ ही उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा सुनाई है। दोनों पर 2-2 हजार का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने आज सुबह साढ़े 11 बजे दोनों को दोषी करार दिया, जबकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया था। विधायक के वकील दरोगा सिंह ने कहा- सजा होने के बाद अब्बास और मंसूर ने 20-20 हजार के बेल बॉन्ड भर दिए, जिसके बाद दोनों को जमानत मिल गई।

जमानत मिलने के बाद जब अब्बास कार से घर के लिए निकले तो पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कहा- आधे घंटे रुक जाइए। इस पर अब्बास ने कहा- सुबह से भूखे हैं, खाना खाने के बाद आ जाऊंगा। पुलिसकर्मी ने जवाब दिया- जिले का बॉर्डर क्रॉस मत करिएगा। अब्बास ने पलटकर जवाब दिया- हम खुद ही फंसे हैं, अब क्या और फंसने का काम करेंगे?

अब्बास को जिस मामले में सजा हुई है, वह 2022 में हुए विधानसभा चुनाव का है। इस दौरान एक चुनावी रैली में अब्बास ने कहा था- सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूं, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है, वहीं रहेगा। पहले हिसाब-किताब होगा। फिर ट्रांसफर होगा।

सजा के ऐलान के बाद कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के साथ एसओजी के जवान भी तैनात रहे। कोर्ट में पेशी से पहले अब्बास के एक समर्थक ने जबरन कोर्ट में घुसने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

अब्बास ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा से विधायक हैं। वह अपने छोटे भाई उमर अंसारी और समर्थकों के साथ शनिवार सुबह 8 बजे कोर्ट पहुंचे। उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन भी किया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किसी भी सांसद-विधायक 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता खुद समाप्त हो जाती है। कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने पर विधानसभा सचिवालय संबंधित सीट को रिक्त करने की घोषणा करता है। इसके बाद इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए भारत निर्वाचन आयोग को उप-चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा जाता है।

संपादकीय : वाजिब चिंता

दुनिया फिलहाल जिस संवेदनशील दौर से गुजर रही है और भारत के सामने अपने कुछ पड़ोसी देशों के अस्थिर रुख की चुनौतियां खड़ी रहती हैं, वैसे में सुरक्षा का हर मोर्चा हर वक्त पूरी तरह चौकस और दुरुस्त रहना एक अनिवार्य तकाजा है। निश्चित रूप से देश की सरकार ने इस संबंध में कोतारी नहीं बरतती होगी। लेकिन यह ऐसा मसला है, जिसमें हमेशा ज्यादा बेहतर करने की जरूरत होती है, कमियों पर ध्यान देना जरूरी होता है। इस लिहाज से देखें तो देश के वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को महत्त्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं के तहत संसाधनों की खरीद और आपूर्ति को लेकर जो सवाल उठाए हैं, उन पर गौर किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने रक्षा सौदों में आपूर्ति में देरी पर चिंता जाहिर करते हुए घरेलू रक्षा क्षेत्र पर गंभीरता से विचार करने के लिए जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वायुसेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं के वादे तो किए गए, लेकिन निर्धारित समय में एक भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी। जबकि बढ़ती चुनौतियों और संवेदनशीलता के मद्देनजर देखें तो समय सीमा सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। सवाल है कि जिस मसले पर सरकार को अपनी ओर से चुनौतियों की पहचान और उसका हल निकालने की पहल करनी चाहिए, उसकी फिक्र वायुसेना प्रमुख को जाहिर करने की जरूरत क्यों पड़ी। यह छिपा नहीं है कि समूची दुनिया में अलग-अलग देशों के बीच समीकरण किस तेजी से बदल रहे हैं कारणों पर बहस हो सकती है, लेकिन यह जगजाहिर है कि अचानक पैदा हुई परिस्थितियों में किसी देश के सामने टकराव से लेकर युद्ध तक के हालात में सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। ऐसे में अगर सैन्य बलों की ओर से परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने पर चिंता जाहिर की जाती है, तो यह सरकार के लिए तत्काल विचार करने और कमियों पर गौर करने का मामला होना चाहिए। वायुसेना प्रमुख की यह बात बेहद अहम है कि युद्ध का चरित्र बदल रहा है तो हर दिन हम नई तकनीकें देख रहे हैं। जाहिर है, इसी मुताबिक खुद को तैयार रखने की जरूरत है। भारत ने कई मौकों पर इस तरह की चुनौतियों को बेहद करीब से देखा और इसका सामना किया है, जिसमें पाकिस्तान या चीन जैसे पड़ोसी नाहक ही टकराव जैसे हालात पैदा करते रहते हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान को किसी भी समय संघर्ष विराम का उल्लंघन करने में हिचक नहीं होती, तो चीन की गतिविधियां भी भारत के लिए चिंता का कारण रही हैं। ऐसे में सीमा पर कब कैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं, यह तय कर पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा तय हो जाए, लेकिन उसकी आपूर्ति और तैनाती के समय को लेकर सजगता नहीं बरती जाए, तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? पिछले कुछ वर्षों के दौरान युद्ध और तकनीकी के मोर्चे पर दुनिया भर में जिस तरह के बदलाव आए हैं, उसमें जरूरत इस बात की है कि सेना को सभी और नए जरूरी साजो-सामान से लैस किया जाए। रक्षा परियोजनाओं के तहत अगर किसी संदर्भ में वादे किए जाते हैं तो उन्हें समय पर पूरा करने को लेकर भी उतनी ही सजगता होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में तकनीकी और संसाधनों के विकास के मामले में आत्मनिर्भरता सबसे बेहतर समाधान है, लेकिन तात्कालिक जरूरतों को तुरंत पूरा करने के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

आखिरकार इंसाफ

उतराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में को अदालत शुक्रवार के फैसले से यह साफ है कि अगर जांच की दिशा सही हो और आरोपियों के प्रति कोई रियायत नहीं बरती जाए, तो इंसाफ मिलना संभव है। दरअसल, एक रिजार्ट में काम करके अपने परिवार का सहारा बनी अंकिता की हत्या के बाद जांच का सिरा जिस दिशा में जा रहा था, उसमें तब यह लगा था कि आरोपी बच निकलेंगे। करीब तीन साल पहले अंकिता की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हत्याकांड का गंभीर पहलू यह भी था कि एक आरोपी रसूखदार नेता का बेटा था शायद इसीलिए मामले को दबाने की भी कोशिश की गई। लेकिन अदालत के सजग रुख और जांच की दिशा की वजह से तीन आरोपियों को दोषी साबित किया जा सका और उन्हें कोटद्वार की अदालत ने उम्रकैद की सजा दी। इससे पहले इस मामले में विशेष जांच दल यानी एसआइटी भी बनाई गई थी। हालांकि तब उस पर भी सवाल उठे थे और लोगों ने सीबीआइ जांच की मांग की थी। अब अदालत के फैसले के बाद अगर इसे अंकिता के परिवार को इंसाफ मिलने और सच की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, तो यह स्वाभाविक ही है । यह फैसला उन परिवारों के लिए एक उम्मीद और राहत है, जिनकी बेटियां घरों से दूर पढ़ने या नौकरी करने निकलती हैं और अपने सपने साकार करना चाहती हैं। यह दुखद है कि आज जिस विकसित और आधुनिक समाज की बात होती हैं, वहां आज भी स्त्रियों को कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है । हमारे समाज में बेटियों के लिए जोखिम का दायरा इतना बड़ा है कि कब धोखा देकर बहला-फुसला कर या दबाव डाल कर या फिर धमका कर उनको शिकार बनाया जाएगा, इसका उन्हें अनुमान तक नहीं होता। एक रिजार्ट में काम करने वाली अंकिता की हत्या इसका स्पष्ट उदाहरण है । अपना भविष्य संवारने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए संघर्ष कर रही युवतियों पर पर घात लगाए पुरुषों के लिए कोटद्वार की अदालत का फैसला स्वागतयोग्य है और एक चेतावनी है कि कानून सबके लिए बराबर है।

झूठ का धुआं, फरेब का गुबार, तंबाकू लाइसेंस खुद देती है सरकार और हर साल आज के दिन मनता है "तंबाकू निषेध दिवस"



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। देशभर में तंबाकू के दुष्प्रभावों पर सरकार और स्वास्थ्य संस्थान लोगों को आगाह करने में जुटे हैं। टीवी चैनलों पर बड़े-बड़े विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, "तंबाकू से होने वाली बीमारियों से बचें," "स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू छोड़ें," और स्कूल-कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सब जगह यही सन्देश है – तंबाकू से दूरी बनाओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि जिस तंबाकू को सरकार दिन-रात हानिकारक बताती है, वही तंबाकू सरकार के लाइसेंस के तहत ही बाज़ार में आता है। हाँ, यह सच है कि भारत सरकार तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और निर्यात के लिए खुद लाइसेंस देती है। यानी तंबाकू बेचने वाली दुकानें, कंपनियां, वे सब सरकार की अनुमति से ही काम करती हैं। इसे लेकर कोई गुप्त बात नहीं, यह पूरी तरह कानूनी है और सरकार इससे भारी राजस्व भी वसूलती है। यहां तो मज़ेदार विरोधाभास है – एक तरफ सरकार सालाना करोड़ों का टैक्स तंबाकू से वसूलती है, वही दूसरी तरफ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाकर लोगों को तंबाकू छोड़ने की सलाह देती है। जैसे कोई डॉक्टर मरीज को ज़हर की दवा देते हुए कहे, "इसे मत लेना, ये आपके लिए हानिकारक है।" सरकार की यह नीति बिल्कुल वैसी ही है जैसे घर के दरवाज़े पर ताले लगाकर चाबी बाहर ही रख देना। क्योंकि जब तक तंबाकू उद्योग को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, तब तक तंबाकू की बिक्री थमेगी नहीं, और जनता सुरक्षित नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रतिबंध का मतलब होगा कि सरकार को भारी राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा। शायद इसी कारण तंबाकू उद्योग पर एक तरह की "सरकारी छूट" बनी रहती है। वास्तविकता यह भी है कि तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मौतों का बोझ हर साल देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी पड़ता है, लाखों लोगों की जान जाती है, मगर इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार तंबाकू से वसूले गए टैक्स पर निर्भर रहती है। इसलिए तंबाकू निषेध दिवस पर लगाई जाने वाली घोषणाएं, जागरूकता अभियान और बड़े-बड़े पोस्टर बस एक दिखावा बनकर रह जाते हैं। इस दुविधा को दूर करने के लिए जरूरी है कि सरकार न केवल तंबाकू के स्वास्थ्य खतरों के खिलाफ कठोर कदम उठाए, बल्कि तंबाकू उत्पादन और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण भी सुनिश्चित करे। तभी तंबाकू छोड़ने का संदेश जनता के दिलों तक पहुंच पाएगा और केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह जाएगा। वरना यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा — सरकार धुएं में लिपटी नीति बनाएगी, तंबाकू के कारण मौतों पर अफसोस जताएगी, लेकिन राजस्व के लालच में ही तंबाकू को लाइसेंस देती रहेगी और साल में एक दिन "तंबाकू निषेध दिवस" मनाकर जनता को सलाह देती रहेगी कि तंबाकू छोड़ो।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिलेभर में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई, 5000 से अधिक प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त



24 न्यूज अपडेट

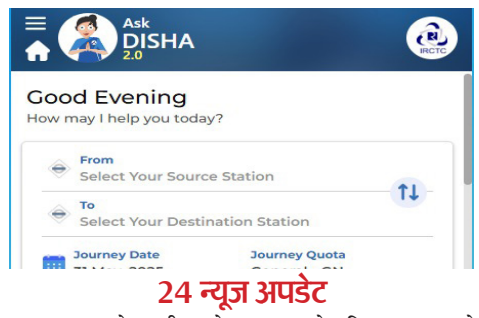
उदयपुर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिलेभर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर कोटपा अधिनियम (COTPA Act) के तहत चालान और जब्ती कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य के निर्देशन में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से की गई। अधिकारियों ने बताया कि 31 मई से 14 जून तक चलने वाले तंबाकू नियंत्रण पखवाड़े के दौरान प्रतिदिन जन-जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ कोटपा अधिनियम के तहत निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि न सिर्फ उदयपुर शहरी क्षेत्र में बल्कि समूचे जिले के सभी खंडों में ब्लॉक स्तर के चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायतें स्थापित करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि पंचायत स्तर तक तंबाकू के हानिकारक प्रभावों की जानकारी पहुंचाकर व्यवहार में बदलाव लाया जाए।

प्रतिबंधित उत्पादों की जब्ती और चालान कार्रवाई- जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ. प्रणव भावसार ने जानकारी दी कि जिले में बिना सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी वाले प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कोटपा अधिनियम की धारा 7 के तहत चालान कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुलदीप यदुवंशी, नेहा बंसल तथा औषधि नियंत्रण अधिकारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभिन्न स्थलों पर निरीक्षण कर 5000 से अधिक सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की जब्ती की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उत्पादों का विक्रय स्वास्थ्य नियमों का घोर उल्लंघन है, जिसके लिए दंडात्मक प्रावधान हैं।

जन-जागरूकता के साथ सख्ती भी जरूरी

डॉ. अशोक आदित्य ने बताया कि तंबाकू उत्पादों के सेवन से हृदय रोग, कैंसर, सांस की बीमारी जैसे अनेक गंभीर रोग होते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में आगामी दो सप्ताहों के दौरान शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों, बाजार क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक, रैलियों, पोस्टर प्रतियोगिता, गोष्ठियों और पंपलेट वितरण जैसे जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अब IRCTC टिकट बुकिंग में बोलने से होगा कामः बिना पासवर्ड के सिर्फ आवाज से बुक करें ट्रेन टिकट, जानिए कैसे



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, फीचर डेस्क। अब ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको पासवर्ड याद रखने, लॉगिन स्क्रीन पर समय गंवाने या बार-बार विफल ट्रांजेक्शन से जूझने की जरूरत नहीं। भारतीय रेलवे की आईआरसीटीसी (IRCTC) सेवा ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित AskDISHA 2.0 चैटबॉट को और उन्नत बना दिया है। यह सेवा अब यात्रियों को मात्र अपनी आवाज से ट्रेन टिकट बुक करने, कैंसिल कराने, रिफंड स्टेटस जानने जैसी सुविधाएं दे रही है – वो भी बिना पासवर्ड डाले।

क्या है AskDISHA 2.0?

रेलवे की ओर से 2023 में लॉन्च किया गया AskDISHA 2.0, एक मल्टी-लिंगुअल वॉयस-बेस्ड AI चैटबॉट है जिसे CoRover.ai द्वारा डेवलप किया गया है। यह चैटबॉट न केवल टेक्स्ट इनपुट, बल्कि आपकी आवाज को भी समझ सकता है। यह हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल समेत कई भारतीय भाषाओं में काम करता है।

अब पासवर्ड नहीं, सिर्फ OTP से करें लॉगिन

टिकट बुकिंग के लिए यूजर्स को केवल अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। फिर मोबाइल पर आए OTP से वे AskDISHA 2.0 पर लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।

ये सुविधाएं हैं AskDISHA 2.0 पर

टिकट बुकिंगः बोलकर ट्रेन, तारीख, स्टेशन, सीट क्लास आदि चुनें और टिकट बुक करें।

टिकट कैंसिलेशनः बुक की गई टिकट को केवल कमांड देकर कैंसिल करें।

रिफंड स्टेटसः PNR नंबर से बोलकर जानें कि आपका रिफंड कहां तक पहुंचा।

बुकिंग हिस्ट्रीः पिछली टिकटों का विवरण भी बोलकर जानें।

लाइव ट्रेन स्टेटसः ट्रेनों के रियल टाइम अपडेट्स भी यहीं मिलते हैं।

ऐसे करें टिकट बुक – आसान स्टेप्सः

IRCTC वेबसाइट या ऐप पर AskDISHA 2.0 पर जाएं।

"बुक टिकट" बोलें या टाइप करें।

अपनी यात्रा से संबंधित जानकारी जैसे स्टेशन का नाम, तारीख, क्लास आदि बोलें।

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।

मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें।

भुगतान के लिए UPI/क्रेडिट/डेबिट/नेट बैंकिंग विकल्प चुनें।

टिकट कन्फर्म होते ही SMS और ईमेल से पुष्टि मिल जाएगी।

टिकट कैंसिल कैसे करें?

AskDISHA पर जाएं और "Cancel Ticket" बोलें या टाइप करें।

लॉगिन के बाद बुक की गई टिकटों की सूची दिखाई देगी।

कैंसिल करने वाली टिकट चुनें और कन्फर्म करें।

SMS से कैंसिलेशन डिटेल्स मिलेंगी।

रिफंड स्टेटस ऐसे चेक करेंः

चटबॉट में "Refund Status" बोलें।

कैंसिल टिकट, फेल्ड ट्रांजैक्शन या TDR में से चयन करें।

PNR नंबर बोलें या टाइप करें।

AskDISHA तत्काल रिफंड की स्थिति बताएगा।

मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन



24 न्यूज अपडेट

खेरोदा थाना क्षेत्र के मेनार गांव में 4 दिन पूर्व हुई मारपीट की घटना को लेकर शनिवार को जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। पीड़ित प्रभुलाल मेघवाल ने बताया कि दिनांक 26 मई को रात्रि के समय करीबन एक-डेढ बजे के आस पास ऑमिनी वेन में 6 व्यक्ति आये और अचानक मेरे घर में जबदस्ती घुस गये। उन व्यक्तियों ने गणपत लाल मेघवाल जो पीछे खडा था, उनमें से एक के हाथ में तलवार थी। और दूसरे व्यक्तियों के पास लोहे के सरिये थे। उक्त व्यक्तियों के मेरे जबरन घर में घुस कर साथ में आये व्यक्तियों को गणपत लाल ने कहा कि यही लोग हैं। तभी इन लोगों ने मेरे दोनों पैरों पर सरिये से वार किया जिससे मुझे गभीर चोटे आई व मेरे पत्नी के सिर पर तलवार व सरिये से वार किये जिससे मेरे पत्नी प्रेमी बाई के सिर पर व शरीर पर गंभीर चोटे आई, इस दौरान बदमाशों ने मेरी पुत्री के साथ भी मारपीट की और मेरी पत्नी का मंगलसूत्र छीनकर ले गए, इसका रिपोर्ट मैने खेरोदा थाना में दर्ज करवाई मगर पुलिस ने आरोपियों पर कोई कारवाही नहीं की, पीड़ित और परिवारजन शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा

धारोद गांव के हनुमान मंदिर में चोरी, चोरों ने सीसीटीवी तोड़कर दानपात्र उड़ाया



24 न्यूज अपडेट

सलूम्बर/खेरवाड़ा। सलूम्बर-खेरवाड़ा स्टेट हाईवे पर स्थित धारोद गांव के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को एक बार फिर चोरों ने अपना निशाना बनाया। गुरुवार देर रात करीब 1 बजे अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के सीसीटीवी कैमरे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर परिसर में जब ग्रामीणों ने अगली सुबह तोड़फोड़ और दानपात्र टूटा देखा, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी मनीष खोईवाल सहित पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोरों ने मंदिर के दानपात्र को निशाना बनाते हुए उसमें रखी करीब एक लाख रुपये नकद राशि चुरा ली है। मंदिर समिति और ग्रामीणों का कहना है कि यह चोरी की चौथी वारदात है, जब इसी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। इससे पहले भी मंदिर में तीन बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस बार चोरों ने पहले सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त किया, जिससे उनकी पहचान न हो सके, और फिर आसानी से दानपात्र को तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ अहम सुराग जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की टीमें संभावित संदिग्धों की तलाश में क्षेत्र में दबिश दे रही हैं। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भय और आक्रोश दोनों व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मंदिर की सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम किए जाएं और इस बार चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए।

सहस्त्र औदीच्य समाज के 31 बटुकों ने विधिवत धारण की यज्ञोपवीत, भव्य आयोजन में उमड़ा समाज



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सहस्त्र औदीच्य समाज द्वारा शनिवार को सेक्टर 11 स्थित आशीष वाटिका में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर समाज के 31 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि-विधान के साथ जनेऊ धारण कर अपने जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार को पूर्ण किया।कार्यक्रम में सहस्त्र औदीच्य समाज की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा ने बताया कि यह आयोजन समाज की परंपराओं और संस्कारों को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि समाज द्वारा हर वर्ष सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों की भागीदारी रहती है।इस बार आयोजन की विशेषता यह रही कि इसमें न केवल उदयपुर, बल्कि राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सहित अन्य जिलों से भी समाज के बटुकों ने भाग लिया। सहस्त्राबाती समाज के प्रतिनिधि श्री दिनेश दवे ने बताया कि इस वर्ष का आयोजन और भी व्यापक और भव्य रूप में किया गया है, जिससे समाज में एकता और संस्कारों की भावना और प्रबल हो। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं और युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं ने पारंपरिक भजनों और गीतों से वातावरण को आध्यात्मिक बनाया, जबकि युवाओं ने आयोजन की व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई।कार्यक्रम के अंत में सभी बटुकों को समाज की ओर से आशीर्वाद पत्र एवं उपहार प्रदान किए गए। यह आयोजन न केवल धार्मिक संस्कार की पूर्ति का अवसर रहा, बल्कि समाज की एकता, संस्कृति और सामूहिकता का प्रतीक बनकर सामने आया।

राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 69, छोटे बच्चे भी आए जद में, कोकून इफेक्ट से रोक सकते हैं संक्रमण



24 न्यूज अपडेट

जयपुरः राजस्थान में कोरोना केसेज लगातार बढ़ रहे हैं. बीते 24 घंटो में राजस्थान में कोरोना के 15 नए केस दर्ज हुए हैं. जिसके बाद राजस्थान में शुक्रवार तक कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 69 हो चुकी है. इन आंकड़ों में खास बात ये है कि इस बार भी कोरोना छोटे बच्चों को अपने संक्रमण की चपेट में ले रहा है. प्रदेश में अभी तक 5 बच्चे इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. जिसमें नवजात बच्चे भी शामिल हैं.

राजस्थान के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण पाटनी ने बताया कि अभी तक कोरोना के वेरिएंट को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आयी है. इसलिए छोटे बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है. लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव भी पेरेंट्स को नहीं होना है और बच्चों में डर या पैनिक की भावना नहीं आने देनी है. प्रदेश में 16 दिन और 2 माह का नवजात भी पॉजिटिव पाया गया है. जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

कोकून इफेक्ट से बचाव संभवः डॉ पाटनी का कहना है कि छोटे बच्चे जल्द किसी भी संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं. खासकर नवजात बच्चे. ऐसे में कोकून इफेक्ट से नवजात बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सकता है. कोकून इफेक्ट में नवजात बच्चो को बाहरी लोगों से बिलकुल दूर रखा जाता है. इसके अलावा बच्चे की जो देखरेख करता है, उसे भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए. इसके अलावा SMS यानि सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन के जरिए आप बच्चों को कोरोना से बचाए रख सकते हैं.

नए वैरियंट की पुष्टिः राजस्थान में कोरोना के नए वैरियंट की पुष्टि हो चुकी है. दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना मरीजों के सैम्पल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए पुणे स्थित एनआईवी लैब में भेजे गए थे. जिसमें XFG और LF.7.9 के 2 केस मिले हैं. बताया जा रहा है की भारत के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में इन दिनों इन दोनों वैरियंट के केस ज्यादा आ रहे हैं.

अभी तक ये स्थितिः प्रदेश में अब तक कोरोना के 69 केस सामने आ चुके हैं. जिसमें अजमेर से 2, बालोतरा से 2, बीकानेर से 5, दौसा से 1, डीडवाना से 5, जयपुर से 33, जोधपुर से 8, फलौदी से 1, सवाईमाधोपुर से 1, उदयपुर से 10 और एक अन्य केस एमपी से सामने आया है.

भारतीय विमान गिरने के सवाल पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयानः सवाल विमानों की संख्या का नहीं, कारण और सीख का है



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, नेशनल डेस्क। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के दावों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें तुरंत सुधारा और दो दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से प्रभावी तरीके से निशाना बनाया। ब्लूमबर्ग के सवालों के जवाब में जनरल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के दावे पूरी तरह गलत हैं। संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि भारत ने संघर्ष से क्या सीखा और अपनी सैन्य रणनीतियों को कैसे मजबूत किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे संघर्ष के दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत कभी नहीं आई, जो एक राहत की बात है। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि उनकी सेना ने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। बाद में यह दावा बढ़ाकर 6 कर दिया गया। भारत ने इन दावों को खारिज कर दिया। इससे पहले एयर मार्शल अवधेश भारती से भी राफेल के क्रैश या मार गिराए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कोई पुष्टि नहीं की। जनरल चौहान ने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भी कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि अब भारत बिना रणनीति के कोई भी कदम नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंधों का जो दौर कभी प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में बुलाकर शुरू हुआ था, वह अब खत्म हो चुका है। जब बदले में सिर्फ दुश्मनी मिले, तो दूरी बनाना ही समझदारी है। उन्होंने बताया कि आजादी के समय पाकिस्तान कई सामाजिक व आर्थिक पैमानों पर भारत से आगे था, लेकिन अब भारत हर मोर्चे पर उससे आगे निकल चुका है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति और आत्मनिर्भरता की नीति का परिणाम है। शांगरी-ला डायलॉग में जनरल चौहान ने 'भविष्य के युद्ध' विषय पर बात रखते हुए बताया कि अब युद्ध केवल भूमि, जल और वायु तक सीमित नहीं हैं, बल्कि साइबर और अंतरिक्ष भी नए युद्धक्षेत्र बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्वदेशी तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम और घरेलू नेटवर्क-रडार प्रणाली जैसी क्षमताएं शामिल थीं। उन्होंने बताया कि युद्ध के दौरान अफवाहें और फर्जी खबरें एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आईं। भारत की रणनीति रही कि बिना जल्दबाजी के, तथ्यों के साथ सटीक जानकारी साझा की जाए। इस ऑपरेशन की शुरुआत में मीडिया से संवाद करने की जिम्मेदारी दो महिला अधिकारियों को सौंपी गई, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी तत्कालीन सैन्य कार्रवाई में व्यस्त थे। जनरल चौहान ने जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ समेत कई देशों के रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस संवाद ने भारत की सैन्य नीति और रणनीतिक दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर और अधिक सुदृढ़ किया।

रिश्वत लेते पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक गिरफ्तार, ACB ने शिकायत पर की ट्रैप कार्रवाई



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, जयपुर। सीकर में शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक दीपक अग्रवाल को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि दीपक अग्रवाल विभागीय कर्मचारियों से तनख्वाह बनाने के नाम पर पैसों की मांग करता था। जब कोई कर्मचारी मासिक बंधी देने से इंकार करता, तो राजनीतिक रसूल के बल पर उसे ट्रांसफर की धमकी दी जाती थी। जानकारी के अनुसार, दीपक अग्रवाल अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जब कर्मचारी फील्ड ड्यूटी के लिए ऑफिस जाते थे, तो उन्हें अनुपस्थित रहने का कारण बताने का नोटिस जारी करता और उनकी तनख्वाह रोक देता था। इस दबाव और धमकियों से परेशान होकर विभाग का एक कर्मचारी जयपुर स्थित एसीबी को शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सीकर शहर के कल्याण कॉलेज के सामने सुख सागर अपार्टमेंट की पार्किंग में दीपक अग्रवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी से एसीबी पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

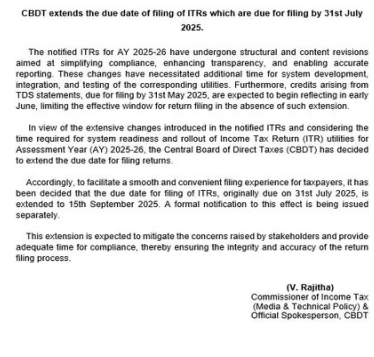
शादी, उत्सव पर स्प्रे कर फाहे उड़ाने की परंपरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक : राज्यपाल बागड़े



24 न्यूज अपडेट

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने तंबाकू मुक्त राजस्थान के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों को छोड़ने के लिए संयम और मन की जरूरत है। उन्होंने तम्बाकू सेवन करने वालों को टोकेने रोकने और इसके दुष्परिणाम बताने के लिए माहौल बनाने पर जोर दिया है। बागडे शनिवार को भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में "विश्व तंबाकू निषेध दिवस" पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा तंबाकू सेवन वालों को इसके नहीं लेने से रोकेंगे तभी सार्थक परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि तंबाकू लेने वाले नहीं माने तो प्रेम से समझाएं, इसके दुष्परिणाम बताएं। इसी से तंबाकू मुक्त राजस्थान की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे।राज्यपाल ने शादी, उत्सव पर स्प्रे कर फाहे उड़ाने की परंपरा को भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने कहा कि स्प्रे से रूई के फाहों जैसी वस्तुओं के साथ प्लास्टिक सूक्ष्म कण मुंह, नाक से शरीर में जाते हैं। यह हानिकारक है। उन्होंने कहा कि तंबाकू पाउच पर चित्र बनाकर लिखा होता है कि इसे लेने से कैंसर होता है फिर भी लोग सेवन करते हैं। यह बुद्धिमानों की बुद्धि से दुश्मनी है। इससे पहले राज्यपाल ने "तंबाकू छोड़ो ,कैंसर से मुक्ति पाओ" लघु फिल्म का लोकार्पण किया।

आयकर विभाग ने रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया की खोली राह, ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी



CBDT extends the due date of filing of ITRs which are due for filing by 31st July 2025.

The notified ITRs for AY 2025-26 have undergone structural and content revisions aimed at simplifying compliance, enhancing transparency, and enabling accurate reporting. These changes have necessitated additional time for system development, integration, and testing of the corresponding utilities. Furthermore, credits arising from TDS statements, due for filing by 31st May 2025, are expected to begin reflecting in early June, limiting the effective window for return filing in the absence of such extension.

In view of the extensive changes introduced in the notified ITRs and considering the time required for system readiness and rollout of Income Tax Return (ITR) utilities for Assessment Year (AY) 2025-26, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the due date for filing returns.

Accordingly, to facilitate a smooth and convenient filing experience for taxpayers, it has been decided that the due date for filing of ITRs, originally due on 31st July 2025, is extended to 15th September 2025. A formal notification to this effect is being issued separately.

This extension is expected to mitigate the concerns raised by stakeholders and provide adequate time for compliance, thereby ensuring the integrity and accuracy of the return filing process.

(V. Rajitha)
Commissioner of Income Tax
(Media & Technical Policy) &
Official Spokesperson, CBDT

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आरंभ कर दिया है। विभाग ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए बताया कि ITR-1 'सहज' और ITR-4 'सुगम' फॉर्म की Excel यूटिलिटी अब करदाताओं के लिए उपलब्ध है। यह सुविधा अब https://www.incometax.gov.in पोर्टल पर उपयोग की जा सकती है। विभाग ने यह सूचना सोशल मीडिया मंच X (पूर्व ट्विटर) पर साझा की, जिसमें कहा गया— "टैक्सपेयर्स ध्यान दें, ITR-1 और ITR-4 की Excel यूटिलिटी अब उपलब्ध है।"

किन्हें किस फॉर्म का उपयोग करना चाहिए?

ITR-1 (सहज): यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख या उससे कम है और जो वेतन, एक घर से किराया, बैंक ब्याज या 5000 रुपये तक की कृषि आय अर्जित करते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सीमा 1.25 लाख तक की होनी चाहिए।

ITR-4 (सुगम): यह फॉर्म ऐसे रेजिडेंट व्यक्तियों, HUFs और फर्म्स के लिए है जो 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम अपनाते हैं। इनकी वार्षिक आय 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छोटे व्यापारी, प्रोफेशनल्स, ऑटो ऑपरेटर आदि इसके पात्र हैं।

टैक्सपेयर्स को राहतः रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख 15 सितंबर

इस साल रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। सीए आनंद जैन के अनुसार, यह निर्णय अत्यंत राहतकारी है क्योंकि पोर्टल पर कई टैक्सपेयर्स को अब तक AIS जैसी जरूरी जानकारी नहीं मिल रही थी और तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही थीं।

ई-फाइलिंग यूटिलिटी क्यों जरूरी है?

ई-फाइलिंग यूटिलिटीज वे उपकरण हैं जो टैक्स रिटर्न को डिजिटल माध्यम से दाखिल करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये दो प्रमुख रूपों में उपलब्ध हैं: ऑनलाइन यूटिलिटीः सीधे पोर्टल पर प्री-फिल्ड डेटा के साथ रिटर्न भरना (अधिकतर वेतनभोगियों के लिए) Excel/JSON यूटिलिटीः प्रोफेशनल्स के लिए, जो ऑफलाइन डेटा तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं।

समय पर ITR नहीं भरा तो क्या होगा?

अगर 15 सितंबर तक रिटर्न नहीं भरा गया, तोः 5 लाख से कम आय वालों पर 1,000 और 5 लाख से अधिक आय वालों पर 5,000 की पेनाल्टी लगेगी। साथ ही, देरी पर 1% मासिक ब्याज भी लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण— हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई भी नुकसान अगले वर्ष कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा।

JEE ADVANCED 2025 : फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बढ़े मौके, 25000 रैंक पर भी मिल सकती है IIT सीट



24 न्यूज अपडेट

कोटाः जेईई एडवांस्ड 2025 का परीक्षा परिणाम 2 जून को जारी किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद 3 जून से जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी. देशभर के आईआईटी संस्थानों में बीटेक और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह प्रक्रिया छह राउंड्स में आयोजित की जाएगी. खास बात यह है कि इस वर्ष फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आईआईटी में प्रवेश के अवसर और भी अधिक रहेंगे.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार, आईआईटी और एनआईटी प्लस सिस्टम के तहत जोसा काउंसलिंग में 20 प्रतिशत सुपरन्यूमेरी सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहती हैं. इस व्यवस्था का फायदा उन छात्राओं को विशेष रूप से मिलता है जिनकी रैंक अपेक्षाकृत अधिक होती है. देव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024 में ऑल इंडिया रैंक 21392 पर भी एक फीमेल कैंडिडेट को काउंसलिंग के पांचवें राउंड में आईआईटी पटना के बीएस इकोनॉमिक्स कोर्स में सीट अलॉट हो गई थी.

आईआईटी में मिल सकता है एडमिशनः देव शर्मा ने बताया कि 2025 में सीटों की कुल संख्या और सुपरन्यूमेरी सीटों की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार लगभग 25 हजार ऑल इंडिया रैंक तक की गर्ल्स कैंडिडेट्स को भी आईआईटी में प्रवेश का अवसर मिल सकता है. जोसा काउंसलिंग में यदि छात्राएं रणनीतिक रूप से स्मार्ट चॉइस फिलिंग करती हैं, तो वे प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में भी प्रवेश पा सकती हैं, भले ही उनकी रैंक अपेक्षाकृत अधिक हो.

स्मार्ट और रणनीतिक चॉइस फिलिंगः उन्होंने कहा कि आईआईटी में प्रवेश की इस प्रक्रिया में छह राउंड्स आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक राउंड में सीट आवंटन का मौका रहेगा. ऐसे में जिन छात्राओं की रैंक 25,000 तक है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. स्मार्ट और रणनीतिक चॉइस फिलिंग उन्हें सफलता के करीब ले जा सकती है.

देव शर्मा ने यह भी सलाह दी कि जो छात्राएं जेईई एडवांस्ड 2025 में सफल रही हैं, वे जल्द ही जोसा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और चॉइस फिलिंग के दौरान विभिन्न आईआईटी संस्थानों और कोर्सेस की कटऑफ का गहन अध्ययन करें. इस विश्लेषण के आधार पर ही विकल्प भरना ज्यादा प्रभावी रहेगा.

नकदी के जाल में फंसा जोधपुर का निजी अस्पताल, इनकम टैक्स की दबिश में करोड़ों बरामद



24 न्यूज अपडेट

जोधपुर। शहर के नामचीन वरदान हॉस्पिटल में शुक्रवार रात इनकम टैक्स विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल परिसर व संबंधित ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई की जड़ में एक 7 करोड़ रुपये का सौदा है, जिसमें से 4 करोड़ रुपये की रकम कथित रूप से काले धन के रूप में दी जा रही थी। इस सौदे में अस्पताल का नाम भी दर्ज है, जिसे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के बीच ट्रांसफर किया जा रहा था। आयकर विभाग को इस सौदे से जुड़ी पिन-पॉइंट जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, जिसके आधार पर शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे टीम ने अस्पताल परिसर में दस्तक दी। मौके से चार बड़े सूटकेस में भारी नकदी जब्त की गई है, जिसकी गिनती के लिए विशेष कैश काउंटिंग मशीनें मंगाई गईं हैं। छानबीन में यह भी सामने आया कि अस्पताल की रजिस्ट्री कम कीमत पर करवाई गई थी और कागजों में दर्ज लेन-देन की राशि वास्तविक सौदे से काफी कम दर्शाई गई थी। विभागीय टीम ने खरीदार और विक्रेता दोनों को एक ही जगह बैठाकर पूछताछ की, जिससे सौदे में हुई अनियमितताओं की परतें खुलनी शुरू हो गईं। सूत्र बताते हैं कि करोड़ों रुपये की नकदी अभी गिनी जा रही है, और सही आंकड़ा आने में समय लग सकता है। हालांकि, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई एक बड़ी टैक्स चोरी की कड़ी हो सकती है, जिसके अन्य लिंक की भी जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पूरे परिसर में पुलिस बल तैनात रहा और बाहर से अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही थी। शहर के चिकित्सा क्षेत्र में यह छापा चर्चा का विषय बना हुआ है।

सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा कलः181 पदों के लिए दो पारियों में होगा एग्जाम, एक घंटे पहले सेंटर पर मिलेगी एंट्री

24 न्यूज अपडेट

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2024 का आयोजन 1 जून 2025 को अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। कुल 181 पदों के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रथम प्रश्न-पत्र सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और द्वितीय प्रश्न-पत्र दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक आयोजित होगा। दस परीक्षा केन्द्रों पर 2700 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड है। **आयोग के अनुसार-** अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक से या एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही अनुमत होगा। देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट), मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। पहचान पत्र में नवीनतम और स्पष्ट रंगीन फोटो होना आवश्यक है।

आयोग ने अभ्यर्थियों को किसी भी दलाल या मध्यस्थ के बहकावे में न आने की चेतावनी दी है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 और 2635255 पर दी जा सकती है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत अनुचित साधनों के प्रयोग पर आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और चल-अचल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश-पत्र के साथ जारी सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें। सुरक्षा जांच और पहचान सत्यापन में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए समय से पहुंचना सुनिश्चित करें।



नाथद्वारा स्टेशन से शहर तक 9 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रेलवे के पक्ष में दिया निर्णय

96% भूमि अधिग्रहण पूरा, खंडपीठ ने एकलपीठ के स्थगन आदेश को किया निरस्त



24 न्यूज अपडेट

नाथद्वारा। नाथद्वारा रेलवे स्टेशन से धार्मिक नगरी नाथद्वारा शहर तक रेल लाइन बिछाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को रेलवे के पक्ष में फैसला देते हुए भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया और एकलपीठ के स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया। इससे रेलवे को शेष भूमि अधिग्रहण का रास्ता भी साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने माना – राष्ट्रहित के प्रोजेक्ट नहीं रोके जा सकते खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र भाटी व न्यायाधीश सुनील बेनीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे मामलों में स्थगन आदेश राष्ट्रहित व जनसामान्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को नहीं रोक सकते। नाथद्वारा जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने के इस प्रयास को कोर्ट ने जनहित से जुड़ा माना। रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी व अधिवक्ता भानु प्रताप बोहरा और देवेश यादव ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि वर्तमान में नाथद्वारा स्टेशन शहर से 9 किलोमीटर दूर है, जिससे श्रीनाथजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होती है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी

रेलवे ने बताया कि कुल 54 हेक्टेयर में से 96% भूमि अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है, और मुआवजा भी उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा करा दिया गया है। केवल 3 हेक्टेयर भूमि को लेकर कुछ व्यक्तियों ने आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी, जिससे पूरा प्रोजेक्ट जुलाई 2024 से रुका हुआ था। पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 4 जुलाई 2024 और 26 मई 2025 को रेलवे की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी किए थे, जिसमें याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त सुनवाई का अवसर न देने और मंदिर की भूमि को अनुचित रूप से बचाने के आरोप लगाए गए थे। रेलवे ने स्पष्ट किया कि एलाइन्मेंट में बदलाव मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि 381 करोड़ रुपये की लागत बचाने के लिए किया गया, जिससे कोई दुर्भावना नहीं जुड़ी है।

2019 में घोषित हुआ था स्पेशल प्रोजेक्ट

रेल लाइन विस्तार को भारत सरकार ने वर्ष 2019 में स्पेशल प्रोजेक्ट घोषित किया था। 2023 में नए एलाइन्मेंट के साथ अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 40 खातेदारों ने आपत्तियां दर्ज कराईं। 9 अप्रैल 2024 को उपखंड अधिकारी नाथद्वारा ने सभी आपत्तियों को निराधार मानते हुए भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी थी। खंडपीठ के आदेश के बाद रेलवे अब शेष 4% भूमि का भी अधिग्रहण कर सकेगा और नाथद्वारा शहर तक रेल लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण गति से शुरू किया जा सकेगा। इससे श्रीनाथजी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को स्टेशन से शहर तक की 9 किलोमीटर की दूरी तय करने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

भीलवाड़ा यूआईटी निकालेगी 3000 प्लॉट की लॉटरी, रिजर्व प्राइज घटाने की निजी कॉलोनाइजर्स की मांग पर उठे सवाल



24 न्यूज अपडेट

भीलवाड़ाः नगर विकास न्यास (यूआईटी) की ओर से न्यास क्षेत्र में खाली भूखंडों की लॉटरी 2 जून से प्रस्तावित है. भीलवाड़ा के कॉलोनाइजर्स ने लॉटरी के मद्देनजर यूआईटी अध्यक्ष एवं सचिव से डीएलसी रेट (रिजर्व प्राइज) घटाने की मांग की. सरकार ने वर्ष 2024 -25 के बजट में प्रदेश के तमाम न्यास एवं निगम क्षेत्र में खाली भूखंडों की लॉटरी निकालने की घोषणा की थी. इसके चलते भीलवाड़ा में न्यास जून में शहरी क्षेत्र में लगभग 3000 प्लॉट की लॉटरी निकालेगा. इससे आमजन को सस्ते प्लॉट मिलने की उम्मीद जगी है. वहीं, कॉलोनाइजर्स ने यूआईटी अध्यक्ष एवं कलेक्टर जसमीत सिंह संधू व न्यास सचिव ललित गोयल को ज्ञापन सौंप, जिनमें डीएलसी दर घटाने की मांग की गई.

भीलवाड़ा प्रॉपर्टी एवं ब्रोकर्स एसोसिएशन के कैलाश कोठारी ने कहा कि न्यास जून में भूखंडों की लॉटरी निकालेगा. इसमें अचानक रिजर्व प्राइज बढ़ाई, जिसके विरोध में जनहित को देखते हमने न्यास सचिव को ज्ञापन सौंपा. रिजर्व प्राइज बढ़ाना उचित नहीं है. ज्यादा रेट होने के कारण आमजन भूखंड नहीं ले पाएगा. हमने अध्यक्ष व सचिव को ज्ञापन देकर पुनर्विचार करने की मांग की. निजी कॉलोनाइजर को अपने प्लॉट नहीं बिकने का डर तो नहीं सता रहा है, यह पूछे जाने पर कोठारी बोले, हमारे पास कोई प्लॉट का मैटर नहीं है. यह जनहित का मुद्दा है. इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स का व्यक्तिगत हित नहीं है.

मार्केट रेट हाईः न्यास सचिव गोयल ने कहा कि प्रॉपर्टी व्यवसायियों की रिजर्व प्राइज को लेकर बात हमारे आंकड़ों से मेल नहीं खाती है. भीलवाड़ा में मार्केट रेट हाई है. आज यहां निजी कॉलोनियों में 50 से 60 लाख रुपए में भूखंड मिल रहे हैं, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है. निजी कॉलोनी में 45 वर्ग मीटर का प्लॉट भी 20 लाख से कम नहीं मिल रहा, जबकि वही भूखंड न्यास ईडब्ल्यूएस केटेगरी में मात्र डेढ़ लाख रुपए में लॉटरी के जरिए दे रहा है. यादव ने बताया कि बापू नगर में आज व मार्केट रेट में 277 प्रतिशत का डिफरेंस है. वहीं, मोहनलाल सुखड़िया नगर में 344 प्रतिशत का डिफरेंस है. कहीं पर भी निजी कॉलोनियों में 200 से 300 प्रतिशत तक के डिफरेंस से कम नहीं है. न्यास 2 जून से लॉटरी प्रक्रिया शुरू करेगा. 6 या 7 जुलाई को लॉटरी निकाल दी जाएगी.

डर तो नहीं सता रहाः यूआईटी की प्रस्तावित लॉटरी में आमजन को भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा. लॉटरी से सस्ते में भूखंड अलॉट होने की उम्मीद है. यह सवाल भी हवा में तैर रहा है कि यूआईटी की लॉटरी के चलते कॉलोनाइजरों को अपनी कॉलोनी में प्लॉट नहीं बिकने का डर तो नहीं सता रहा है. कॉलोनाइजर जनहित में रिजर्व प्राइज कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा के पीछे कई सवाल उठाए जा रहे हैं.

'सेक्स सॉर्टेड सीमेन' योजना में दो माह में 23,500 पशुओं का टीकाकरण, 95 %से अधिक मामलों में मादा बछड़ी जन्मने की उम्मीद



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। पशुपालन विभाग द्वारा बड़गांव तहसील में चलाए जा रहे खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) रोकथाम अभियान का समापन शुक्रवार को चिकलवास, लखावली और ईसवाल गांवों में शिविर लगाकर किया गया। अभियान के दौरान दो महीनों में 105 गांवों के 23,500 से अधिक गाय-भैंसों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का भी लाभ

ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिसर डॉ. दत्तात्रेय चौधरी ने बताया कि टीकाकरण कार्य के साथ-साथ मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा भी निःशुल्क किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम वहन की जा रही है और बीमित पशु की मृत्यु की स्थिति में पशुपालकों को 40,000 तक की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। शिविरों के माध्यम से घर-घर जाकर हेल्थ सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए।

नवाचारः सेक्स सॉर्टेड सीमेन योजना से मादा बछड़ी का जन्म होगा सुनिश्चित

पशुपालन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई 'सेक्स सॉर्टेड सीमेन योजना' ने ग्रामीण पशुपालकों में नई आशा जगाई है। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान विधि के माध्यम से 95% से अधिक मामलों में मादा बछड़ी के जन्म की संभावना रहती है। डॉ. चौधरी ने बताया कि 30 मई को पालड़ी कटरा गांव में पशुपालकों उदयलाल भेरूलाल और रमेश सुथार की गायों में इसी तकनीक से सीमेन का उपयोग कर कृत्रिम गर्भाधान किया गया, जिससे मादा बछड़ी की जन्म की संभावना अत्यधिक बढ़ गई है। यह योजना विशेष रूप से उन पशुपालकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है जो नर पशु नहीं पालना चाहते। 3500 डोज जिले में उपलब्ध, 20 तहसीलों में फैला नेटवर्क संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, डॉ. सुरेश जैन ने बताया कि योजना की पहली किस्त के रूप में 3500 डोज सेक्स सॉर्टेड सीमेन जिले के 20 तहसीलों के ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिसरों को उपलब्ध कराई गई है। ये डोज संबंधित पशुपालकों को उनके गांव में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। साहीवाल, होल्सटीन और मुर्रा नस्लों का सीमेन उपलब्ध योजना के अंतर्गत गायों के लिए साहीवाल और होल्सटीन नस्ल तथा भैंसों के लिए मुर्रा नस्ल का सीमेन उपलब्ध है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों का संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके। एफएमडी टीकाकरण, मंगला पशु बीमा योजना और सेक्स सॉर्टेड सीमेन जैसी योजनाएं न केवल पशुधन को रोगों से बचाने में सहायक हैं, बल्कि नस्ल सुधार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में भी कारगर साबित हो रही हैं। ग्रामीण पशुपालकों को इनके माध्यम से दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

बांसवाड़ा में कागदी बांध पर आतंकी हमले की मॉक ड्रिलः गोलीबारी और ड्रोन अटैक का सीन, 20 घायल, 5 गंभीर, लेटलतीफी पर जताई नाराजगी



24 न्यूज अपडेट

बांसवाड़ा। भारत-पाक तनाव के बीच बांसवाड़ा जिले में शनिवार शाम एक वास्तविक आतंकवादी हमले जैसी स्थिति को दर्शाती मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल कागदी बांध पर शाम ठीक 5 बजे शुरू की गई, जिसमें ड्रोन और हवाई हमले का सीन तैयार कर, गोलीबारी और विस्फोटों के जरिए एक बड़े आतंकी हमले की झलक प्रस्तुत की गई। मॉक ड्रिल में 20 लोग घायल दिखाए गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर रही। इन्हें तुरंत जिला एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य को बांध क्षेत्र में बनाए गए वैकल्पिक उपचार केंद्र पर प्राथमिक चिकित्सा दी गई।

प्रशासनिक टीमों की प्रतिक्रिया समय रही चिंता का विषय

ड्रिल के जरिए आपात स्थिति में प्रशासन की तत्परता की जांच की गई, जिसमें प्रारंभिक प्रतिक्रिया समय पर कई सवाल खड़े हो गए: 6वें मिनट पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। 10 मिनट बाद पुलिस और जिला प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे। 20वें मिनट में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आई, जबकि ब्लास्ट के बाद सबसे पहले अग्निशमन की आवश्यकता थी। 26 मिनट बाद चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची, तब तक गंभीर रूप से घायल लोग चिल्लाते और तड़पते रहे। यह देरी प्रशासनिक समन्वय और आपात सेवाओं की तत्परता पर सवाल खड़े करती है।

भारत-पाक तनाव के परिप्रेक्ष्य में हुआ अभ्यास

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और 7 मई को भारत द्वारा च्वज्ञ और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक (ऑपरेशन सिंदूर) के बाद भारत-पाक के बीच माहौल तनावपूर्ण है। इसी पृष्ठभूमि में सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन शील्ड नामक मॉक ड्रिल के तहत यह अभ्यास किया।

क्या होती है मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज?

मॉक ड्रिल एक पूर्व नियोजित आपातकालीन अभ्यास होता है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता की जांच की जाती है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज के तहत इलाके की बिजली बंद कर यह आकलन किया जाता है कि युद्ध या हमले की स्थिति में शत्रु के निशाने से बचने के लिए किस तरह रोशनी रहित रणनीति अपनाई जा सकती है।

उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाओं के लिए महेंद्र सिंह सारंगदेवोत व अमृत असौड़ा का सम्मान

निस्वार्थ भाव से कि गई सेवा ही सम्मान के हकदार



24 न्यूज अपडेट

राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर शहर ने उत्कृष्ट नर्सिंग सेवा सम्मान जीएनटीसी सभागार में रखा गया। सम्भागीय अध्यक्ष नरेश पूर्बिया ने बताया कि जिलाध्यक्ष पवन कुमार दानाध्यक्ष व प्रवीण चरपोटा ने अस्पताल में उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाओं के लिए सिनियर नर्सिंग आंफिसर महेंद्र सिंह सारंगदेवोत व अमृत असौड़ा का उपरणा ओढ़ाकर, साफा पहनाकर,शोल ओढ़ाकर, स्मृति चिन्ह व प्रसंशा पत्र भेंटकर स्वागत व अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नर्सिंग अधीक्षक गीता आहारी, ओमप्रकाश पालीवाल, भगवान सिंह गहलोत,भगवत सिंह,अमीन खान, नूरानी मेइडा, जितेंद्र भटनागर थे । विशिष्ट अतिथि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत आमेटा, संरक्षक रमेश मीणा, सम्भागीय अध्यक्ष नरेश पूर्बिया, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यवीर सिंह तंवर थे। सभी वक्ताओं ने उनकी उत्कृष्ट सेवाओं की खुब सराहना की। निस्वार्थ भाव से कि गई सम्मान के हकदार हैं महेंद्र सिंह का संगठन को मजबूत बनाने में किए गए प्रयास की खुब प्रशंसा हुई। संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष परमार ने किया। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण चौहान, राजेश चौधरी, नारायण सिंह, डॉ विपिन मेहता, डॉ रणजीत सिंह बैरवा,हरिश चौबीसा, रमेश पंजाबी,मंगला जोशी, पूर्व नर्सिंग अधीक्षक दिनेश गुप्ता, सुरजमल सालवी, श्याम मेघवाल,प्रेम प्रकाश मेहता,मदन सिंह राणावत, अनिल धावना, प्रदीप मेहता, मोहनलाल सालवी, मनोज जिनगर, कृष्ण अवतार गुप्ता, ओमप्रकाश खंडेलवाल, दिनेश सिसोदिया, देवी लाल सालवी, प्रवीण पूर्बिया,उषा पड़वाल, सुर्य कांता मीणा, चंद्र कांता तलेसरा, निर्मला सौलंकी,रमीला तराल, सुनीता खंडेलवाल, बिंदु अल्फोस,नीतू मेवाड़ा, दीपक मेघवाल सहित सैकड़ों नर्सेज उपस्थित थे।

वार्षिकोत्सव स्वर 2025 में रंगारंग प्रस्तुति, पुरस्कार पाकर प्रतिभागियों के खिले चेहरे



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मंत्रम टीचर्स ट्रेनिंग कालेज उदयपुर का वार्षिकोत्सव स्वर 2025 धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। किसी अपने अंदाज में गाने गाए तो किसी ने डांस कर दर्शकों का मन मोह लिया। प्राचार्य डॉ पंकज पारीक ने बताया कि मुख्य अतिथि समर्थ नागौरी, कविराज श्रेणीदान चारण , लक्ष्मण पुरी महाराज व महेंद्र थे। विशिष्ट अतिथि राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर के जिलाध्यक्ष पवन कुमार दानाध्यक्ष व सम्भागीय अध्यक्ष नरेश पूर्बिया थे। कार्यक्रम प्रभारी डॉ राखी ने बताया कि प्राचार्य डॉ पंकज पारीक की उपस्थिति में सभी अतिथियों ने वर्ष भर में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम में विजेताओं को प्रसंशा पत्र,मेडल व पुरस्कार से सम्मान किया गया। पुरस्कार पा कर विजेताओं के चेहरे खिल उठे। कविराज श्रेणीदान चारण ने महाराणा प्रताप के शौर्य की कविताएं सुनाकर खुब तालीया बटोरीं। नरेश पूर्बिया ने कहा कि विधार्थी जीवन में शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों में महारथ हासिल करने से समाज में पहचान बनती हैं।आने वाले समय में आप देश के भावी शिक्षक बनेंगे।आपका उद्देश्य राष्ट्रभक्त व संस्कारवान नागरिक तैयार करना है। संचालन बाला पानेरी ने किया।

समाचार भेजने के लिए हमारी मेल आई-डी पर संपर्क करें -

desk24newsupdate@gmai.com

उदयपुरः नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक चेयरमैन कैलाशचंद्र अग्रवाल को सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान सम्मान



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर : चार दशक से दिव्यांगता और मानवता के लिए सेवारत नारायण सेवा संस्थान को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया. नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक चेयरमैन पद्मश्री कैलाशचंद्र अग्रवाल 'मानव' को दिल्ली में प्रतिष्ठित लक्ष्मीपत सिंघानिया आईआईएम लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान श्रेणी में दिया गया.

प्रशान्त अग्रवाल ने पुरस्कार ग्रहण कियाः समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी. वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र दिया. नारायण सेवा संस्थान की ओर से अध्यक्ष प्रशान्त अग्रवाल ने पुरस्कार ग्रहण किया. प्रशान्त अग्रवाल ने कहा यह सम्मान हमारे संस्थापक चेयरमैन एवं गुरु कैलाश मानव की सेवा मार्ग की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है. यह न केवल संस्थान के लिए गौरवपूर्ण बल्कि लाखों दिव्यांगों की आशा व आकांक्षाओं का सम्मान है.

इस अवसर पर जेके ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भरत हरि सिंघानिया, वाइस प्रेसिडेंट रघुपति सिंघानिया, पुरस्कार जूरी चेयरमैन एनके सिंह और आईआईएम लखनऊ निदेशक प्रो. एमपी गुप्ता मौजूद थे. नारायण सेवा संस्थान बीते चार दशक से निशुल्क कृत्रिम अंग वितरण, दिव्यांगों के ऑपरेशन, पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सेवा कार्य कर रहा है. नारायण सेवा संस्थान की ओर से अब तक लाखों जरूरतमंदों को नया जीवन और आत्मनिर्भरता दी है.

दुष्कर्म की पीड़ा और स्त्री संघर्ष की गूंज है 'कल्याणी': सिनेमैड फिल्म्स की शॉर्ट फिल्म रिलीज



24 न्यूज अपडेट

समाज में महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण और घरेलू दुष्कर्म जैसे संवेदनशील विषयों पर करारा प्रहार करती शॉर्ट फिल्म 'कल्याणी' शुक्रवार को सिनेमैड फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले यू ट्यूब पर रिलीज हुई। महज 27 मिनट की इस फिल्म में एक बड़ा सामाजिक संदेश बेहद संजीदगी और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

फिल्म की कहानी युवा राइटर और डायरेक्टर हिया शर्मा ने लिखी है, जिन्होंने पीड़िता की मुख्य भूमिका भी खुद निभाई है। उनके दमदार अभिनय ने किरदार को जीवंत बना दिया। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का शोषण अक्सर अपने ही घर की चारदीवारी में, अपनों के द्वारा होता है और वह भी चुप्पी और शर्म के आवरण में दबा दिया जाता है। लेकिन ये चुप्पी जब टूटती है तो क्या होता है....यही फ़िल्म की कहानी है।

कैमरामैन आशीष बुंबाड़िया की सिनेमैटोग्राफी फिल्म की गंभीरता और भावनात्मक गहराई को बेहतरीन ढंग से दर्शाती है। एक लाचार मां की भूमिका में कृष्णा शर्मा का अभिनय दर्शकों की आंखें नम कर देता है। अन्य कलाकारों — सावन जैन, ओमपाल सीलन, प्रवर खंडेलवाल, सुनीता शर्मा और चेष्टा मेनारिया ने भी अपने अभिनय से फिल्म को प्रभावशाली बनाने में योगदान दिया।

'कल्याणी' न केवल एक कहानी है, बल्कि यह उन असंख्य पीड़िताओं की आवाज है जो आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है और समाज में बदलाव की जरूरत को उजागर करती है।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।